INFORMATION TO THE HOUSE

Statement re. Broadcasting of documentary titled 'India's Daughter' by BBC Four's Storyville

गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) : उपसभापति महोदय, अभी यहां माननीय सदस्यों के द्वारा जो प्रश्न उठाया गया है कि बीबीसी के द्वारा एक डॉक्युमेंटरी रिलीज की जा रही है, उसी के सम्बन्ध में जानकारी देने के लिए मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूँ। मैं उस सम्बन्ध में पूरी डिटेल्ड जानकारी इस सदन के सभी सम्मानित सदस्यों को देना चाहता हूँ। A No Objection Certificate (NOC) to shoot the documentary featuring interview of convicted inmates in Tihar jail of cases related to atrocities against women was given by the Ministry of Home Affairs on 24th July, 2013, and thereafter permissions were given by the jail authorities to shoot the documentary to Ms. Leslee Udwin and Ms. Anjali Bhushan with the following conditions:—

(i) Prior approval of jail authorities is to be taken for publishing the research paper or for releasing the documentary film which is being made for purely social purposes without any commercial interest as conveyed.

(ii) To interview only such convicted prisoners who give written consent.

(iii) The complete unedited footage of shoot in the Tihar Jail premises will be shown to the jail authorities to ensure that there is no breach of prison security.

This documentary *inter-alia* features interview of one of the accused of the Nirbhaya case.

It came to the notice of the jail authorities that the permission conditions have been violated and hence a legal notice was issued to them on 7th April, 2014, to return the unedited footage within 15 days and also not to show the film as it violates the permission conditions. Subsequently, the documentary film was shown to the jail authorities where it was noticed that the documentary film depicts the comments of the convict which are highly derogatory and are an affront to the dignity of women. It was also noticed that the film shown was the edited version and not the unedited as per permission conditions. Hence, they were requested to provide full copy of the unedited film shootout for further review by the authorities and that they were asked not to release or screen the documentary till it is approved by the authorities.

Now, it has come to notice that on March 8, 2015, BBC Four is going to telecast this documentary film. The Government has taken necessary legal action and obtained a restraining order from the court disseminating the contents of the film.

[श्री राजनाथ सिंह]

Our Government condemns the incident of 16th December, 2012 in the strongest possible terms and will not allow any attempt by any individual, group or organization to leverage such unfortunate incidents for commercial benefits. The respect and dignity of women constitute a core value of our culture and tradition. Our Government remains fully committed to ensuring safety and dignity of women.

श्रीमन्, मैं सदन के सभी सम्मानित सदस्यों को यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कल ज्यों ही इस घटना के बारे में मुझे जानकारी मिली, मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत ही हर्ट हुआ था और तुरंत इस सम्बन्ध में जो कन्सर्न्ड अथॉरिटीज़ हैं, मैंने उनसे सीधे बात की थी और हमने आवश्यक इंस्ट्रक्शंस दिये थे। मैंने कहा कि किसी भी सूरत में यह टेलिकास्ट नहीं किया जाना चाहिए और कल ही रात को कोर्ट में जाकर वहां से आदेश प्राप्त किया गया कि यह अब जो कुछ भी टेलिकास्ट किया गया है, इसे रिलीज़ नहीं किया जाए। इतना ही नहीं, मुझे इस बात पर ही आश्चर्य है ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, please. Let him complete. ...(*Interruptions*)...

श्री राजनाथ सिंहः उपसभापति महोदय, मुझे यह भी आश्चर्य है कि किन परिस्थितियों में यह आदेश दिया गया। मैंने यह कहा है कि मैं इसकी पूरी जानकारी चाहूँगा और इस प्रकार के आदेश देने का अब तक का जो भी प्रोसीज़र रहा है, अगर जरूरत पड़ी तो उसको मैं रिव्यू करूँगा और इस प्रकार से भविष्य में किसी को जेल में जाकर और इस प्रकार ...(**व्यवधान**)... रेपिस्ट के इंटरव्यू टेलिकास्ट करने की इजाजत किसी भी सूरत में भविष्य में नहीं दी जायेगी। यह मैं ensure करूँगा। इतना ही नहीं ...(**व्यवधान**)...

श्री नरेश अग्रवाल (उत्तर प्रदेश): उस समय जेल में जो अथॉरिटी थी, उनके खिलाफ क्या ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No. कम्प्लीट करने दीजिए। ...(**व्यवधान**)... Let him finish. ...(*Interruptions*)...

श्री नरेश अग्रवाल : उस जेल के जो Superintendent थे, उन्होंने परमिशन दी। ...(**व्यवधान**)... जिन्होंने परमिशन दी, उनके खिलाफ अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। ...(**व्यवधान**)... आप एक्शन की घोषणा कीजिए, तब तो समझें कि...(**व्यवधान**)...

श्री राजनाथ सिंहः मैं उस पर आ रहा हूँ। ...(**व्यवधान**)... मैं उस पर आ रहा हूँ। ...(**व्यवधान**)...

SHRI P. RAJEEVE (Kerala): One more question. It is reported in the media that the Home Ministry had also given the permission. So, please also tell us whether the Government has taken any action against the officer who has given the permission for this.

श्री अली अनवर अंसारी (बिहार): माननीय मंत्री जी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि रेपिस्ट को अभी तक फांसी पर क्यों नहीं लटकाया गया? उसमें क्यों विलम्ब हो रहा है? ...(**व्यवधान**)... उससे पूरे देश में मैसेज जाता। ...(**व्यवधान**)...

श्री राजनाथ सिंहः यह काम, यह डिसीज़न तो कोर्ट का है। श्रीमन्, इस सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। जो कुछ भी कोर्ट का आदेश है, **...(व्यवधान)...** जो कुछ भी रूल्स और रेग्युलेशंस हैं, यह उनके तहत होगा। **...(व्यवधान)...**

श्री वी. हनुमंत राव (तेलंगाना)ः सर, **...(व्यवधान)...**

श्री अली अनवर अंसारीः सर, जो विदेशी पत्रकार होते हैं, **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: All right. ...(*Interruptions*)... Okay. ...(*Interruptions*)... Ansariji, please. ...(*Interruptions*)... Ansariji. ...(*Interruptions*)...

MS. ANU AGA (Nominated): Sir, can I say something? ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Ansariji, let the hon. Lady Member say something. ...(*Interruptions*)... Ansariji, please. ...(*Interruptions*)... Ansariji, please. ...(*Interruptions*)...

श्री अली अनवर अंसारीः सर, **...(व्यवधान)...** उनको जल्दी परमिशन मिल जाती है। **...(व्यवधान)...**

श्री उपसभापतिः अंसारी जी, आप बैठिए। **...(व्यवधान)...** I have allowed her, a senior hon. Lady Member.

MS. ANU AGA : Sir, I concede that there is an issue of who gave the permission and all that. But the reality is that what the man spoke reflects the views of many men in India. And why are we shying away from that? In everything glorifying India, we are perfect; we are not confronting the issues which need to be really confronted. Suggesting death penalty or banning this movie is not the answer. We have to confront the issue that men in India do not respect women. And, any time there is a rape, blame is put on the woman, that she was indecently dressed and she provoked the men. They are not just the views of the man in the prison; they are the views of many men in India. Let us be aware of it and let us not pretend that all is well.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: All right. ...(*Interruptions*)... Yes, please. ...(*Interruptions*)...

SHRI JAVED AKHTAR (Nominated): Sir, I almost second with her.

श्री उपसभापति : कृपया आप बोलिए।

श्री जावेद अख्तर : सर, सवाल यह है, गुस्सा इस बात पर है कि उस आदमी का इंटरव्यू क्यों लिया गया, गुस्सा इस बात पर है कि उस आदमी ने इतनी गलत बातें क्यों की, गुस्सा इस बात पर है कि यह दुनिया को क्यों बताया जा रहा है कि यह रेपिस्ट इतनी गंदी बातें कर रहा

[श्री जावेद अख्तर]

है। सर, इस तरह की बातें तो मैं इस हाउस में सुन चुका हूँ कि एक औरत अगर इस तरह के कपड़े पहनेगी, एक औरत अगर रात को सड़क पर इस तरह घूमेगी, तो वह trouble invite कर रही है। अच्छा हुआ कि यह documentary बनी है, इसलिए कि हिन्दुस्तान के करोड़ों आदमियों को मालूम हुआ कि वे रेपिस्ट की तरह सोचते हैं। अगर यह गंदा लग रहा है, तो उन्हें अपनी सोच बदलनी चाहिए।

SHRIMATI JAYA BACHCHAN (Uttar Pradesh): Thank you very much, hon. Home Minister. I appreciate what you have done, but I want to know तीन साल हो गए, what justice are you going to give to the memory of this woman who suffered and her family? I don't want any more assurances. तीन साल तक मैंने इस विषय पर बात नहीं की, मगर आज मैं बाध्य हूँ। आप प्लीज़ बताइए कि आप immediate action क्या लेंगे और कब तक लेंगे, अन्यथा you are asking for a very big trouble? और आप देश को यह तो बताइए कि आप safety of women की जो बात कर रहे हैं, वीमेन की dignity को जिस तरह से insult कर रहे हैं, उसके ऊपर तुरंत इसी वक्त आप क्या कार्रवाई करेंगे?

श्रीमती रजनी पाटिल (महाराष्ट्र): सर, बहुत शर्मिंदगी से हमें यह कहना पड़ रहा है कि जिस तरह से कल से बयान आ रहे हैं और हमारे ऊपर moral policing करने वाले ये कौन होते हैं कि कौन-से कपड़े पहनो, क्या करो, क्या नहीं करो? इनका कोई हक नहीं बनता है। मुझे एक बात कहनी है कि मैं freedom of expression को जरूर मानती हूँ और प्रेस का expression भी मानती हूँ, लेकिन प्रेस ने भी इस तरह से ज़बान देकर बहुत बड़ा अन्याय किया है और इस तरह से इस देश की महिलाओं को बड़ी ठेस पहुंचाई है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रेस से भी यह दरख्वास्त करूंगी कि प्रेस को भी इस तरह से मुलाकातें न दिखाते हुए, इंटरव्यू न दिखाते हुए उन्हें भी एक अच्छा कदम उठाने की जरूरत थी।

दूसरी बात यह है कि जब तक हमारे देश के सभी लोगों की इस तरह की मानसिकता नहीं बदलेगी, यह सिर्फ एक आदमी की मानसिकता बदलने से नहीं होगा, बल्कि सभी लोगों की मानसिकता बदलनी चाहिए, माइंडसेट बदलना चाहिए, जब तक हमारी मानसिकता नहीं बदलेगी, तब तक इस प्रकार के कांड होते रहेंगे।

श्रीमती जया बच्चन: आप मानसिकता तो बदलते रहिए, मगर पहले कार्रवाई करके दिखाइए, तुरंत।

SHRIMATI AMBIKA SONI (Punjab): Sir, it is not only a question of how men think about women – it is true, and that is why there is a constant struggle going on– but, in this particular case, we were very surprised as to how those people got permission, when in the last two days this was a burning topic. I am told that the permission was given as a study case, not to be used outside at all, not to get into the public arena, and to be used as an input on how to deal with such criminals. Be it as it may, that may have been the case, but today, inquiry has to be made as to how it all got into the public arena. And, if it is true that this was done as a test case to get inputs on how to deal with such crimes and criminals, then why

was it necessary to give a foreign channel the permission to interview these people? Whatever it is, it is not a question of who gave the permission.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Whoever it is; whoever it is, ...(*Interruptions*)...

SHRIMATI AMBIKA SONI: Please let us not politicize it. ...(*Interruptions*)... Please do not politicize it. I am saying, ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shrimati Nirmala Sitharaman. ...(*Interruptions*)...

SHRIMATI AMBIKA SONI : Don't politicize it. ...(*Interruptions*)... Now, don't politicize it. Sir, I haven't finished. I want...(*Interruptions*)... No, Sir; I haven't finished. ...(*Interruptions*)...

Sir, we have been demanding for a long time that there should be quick trials and quick punishments for such people. When they go on for such a long time, then जैसी मानसिक सोच होती है, वैसी ही वह बाहर निकलती है और सारा atmosphere vitiate होता है।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, thank you very much for giving me this opportunity.

It is an issue on which, I think, there is absolutely no division, if I understand it correctly, whether that side or this side.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yeah, yeah. The House is one on this.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: The sense of outrage that this House rightly feels is being felt by many here, in fact, all of us here, in this House, and also by many outside. There are a few things which I definitely want to put on record. I am very grateful, first of all, to the Home Minister, who gave a very timely and speedy response in the matter. In this statement, which he has given, he has assured the House saying that he has taken the necessary action through the Police, and where necessary, action will also be taken through courts on anything to do with the permission which was given for whatever, the violation which has been done as of the permission and the conditions which were laid. All of them have been violated. On that, he has assured the House that necessary action will be speedily taken. That is one thing.

Secondly, I am fully agreeing with Javed Saheb when he says that this kind of an attitude prevails and there is a need to change the attitudes. I would slightly differ from him. As many men as he would say feel the similar way as the convict has given a statement, there are very many men who are also feeling that this is not acceptable. So, I think, equally, we should be conscious that every member of the

[Shrimati Nirmala Sitharaman]
society will have to slowly but steadily stand up against such outrage. And, in this matter, I would think that Jayaji's concern has to be addressed but through the courts. If I understand very little of the Government, the Government can go only that far and not further in a matter which is already in the court, and all of us would voice our concern that speedy judicial dispensation of justice is required on this matter. I am again very grateful that the Government has taken both the steps, one through the Home Ministry and the second through the Information and Broadcasting Ministry which has given an advisory not to air the programmes. Thank you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Km. Mayawati.

श्रीमती जया बच्चनः सर, डा. टी.एन. सीमा जी भी बोलना चाहती हैं, वह कब से हाथ उठा रही हैं। ...(**व्यवधान**)... She has been involved with this issue and debating for the last three years.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, I will come back.

सुश्री मायावती (उत्तर प्रदेश)ः माननीय उपसभापति महोदय, जो निर्भया कांड हुआ था, वह बहुत ही घृणित और दर्दनाक कांड हुआ था, अपने देश में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में इसकी निन्दा की गई और अभी recently इस कांड को लेकर और खास तौर से इस कांड के जो आरोपी थे, उनसे जो इंटरव्यू लिया गया या फिल्म वगैरह बनाई गई, इस मामले को लेकर वर्तमान गवर्नमेंट ने और खास तौर से माननीय गृह मंत्री जी ने तुरंत जो कदम उठाए हैं, यह सराहनीय है और इसका हम वेलकम करते हैं।

महोदय, इस मामले के आरोपी से जो इंटरव्यू लिया गया या फिल्म वगैरह बनाई गई, इसमें जेल के जिन अधिकारियों ने उनको इसके लिए परमिशन दी, इसमें जिन अधिकारियों का रोल है, माननीय गृह मंत्री जी से मेरा यह कहना है कि आपको इसके लिए एक जांच बैठानी चाहिए। पहले क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, उसके चक्कर में हमें नहीं फंसना चाहिए। इसकी जांच बैठा कर इस मामले को लंबा नहीं लटकाना चाहिए, चाहे तो दस दिन या पंद्रह दिन में, टाइम बाउण्ड इसकी जांच होनी चाहिए और इसमें जो भी दोषी लोग हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त से कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इस किस्म की पुनरावृति न हो। इसके अलावा यह जो मामला है, वह काफी लंबे अरसे से अटका हुआ है, इसलिए सरकार से मेरा यह भी कहना है कि सरकार इस मामले की पैरवी करके जो आरोपी लोग हैं, उनके खिलाफ जल्दी से जल्दी कार्रवाई करे और उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, ऐसी मेरी दरख्वास्त है। धन्यवाद।

DR. T.N. SEEMA (Kerala): Sir, it is unfortunate that only whenever something happens, some tragic incident happens, we discuss these things and the Government expresses its concern, but after that, we forget it very conveniently. This can't go on like this. The woman in this country is frustrated. The system is not working. We are talking about the mindset. The system is not working for the last three years. Nirbhaya Fund is lying unused. Not a single rupee has been spent from Nirbhaya Fund, and this year also, they have allocated ₹ 1,000 crore for this Fund.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shrimati Viplove Thakur is also there. Leave one minute for her also.

DR. T.N. SEEMA: I want to say one thing more. I agree with all the hon. Members who have mentioned about this. This mindset is not only about the convicted or sentenced people or ordinary people; MPs and Ministers also come with derogatory statements on women. But, it is not banned. The respective parties should give punishment and take action against such people.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shrimati Viplove Thakur.

श्रीमती विप्लव ठाकुर (हिमाचल प्रदेश): उपसभापति महोदय, मैं यह कहना चाहती हूँ कि हम होम मिनिस्टर जी के धन्यवादी हैं कि उन्होंने इस पर स्टेटमेंट दी। ...(**व्यवधान**)... मैं यह कहना चाहती हूँ कि जो जस्टिस नहीं मिल रहा, ऐसे केस लंबे होते हैं, इसमें वकीलों का भी हाथ है। ...(**व्यवधान**)...

12.00 Noon

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Time is over. It is time for Question Hour. ...(*Interruptions*)...

श्रीमती विप्लव ठाकुर : सर, यह ...(**व्यवधान**)...

(MR. CHAIRMAN *in the Chair.*)

MR. CHAIRMAN: Question Hour, please. Question No. 91. ...(*Interruptions*)... Just a minute.

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY (Andhra Pradesh): Sir, it is travesty of justice. ...(*Interruptions*)... Sir, this demands that the House should be seized of the matter of urgent public importance. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Renuka ji, the issue has been raised and all sections of the House have expressed... ...(*Interruptions*)... Please sit down.

श्रीमती जया बच्चन : सर, यह बात फिर से ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : देखिए, आपने सुन लिया। ...(**व्यवधान**)...

SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH (Tamil Nadu): We all stand united. ...(*Interruptions*)...

श्री सभापति : देखिए, आपने गृह मंत्री जी का स्टेटमेंट मांगा, फिर मंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया। All sections of the House have expressed their opinion. ...(*Interruptions*)... Now, let us get on with the Question Hour. Question No. 91.

SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH: Sir, it is against the voiceless. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Please sit down.

SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH: I agree with Nirmala Sitharaman ji that... ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Question No. 91. ...(*Interruptions*)... Questioner is not present. Let the answer be laid on the Table. ...(*Interruptions*)...

श्री नरेश अग्रवाल : माननीय चेयरमैन साहब, जो इश्यु उठा था उस पर माननीय गृह मंत्री जी ने स्पष्ट जवाब नहीं दिया। श्रीमन्, फिर ऐसी घटनाएं घटती रहेंगी। अभी WhatsApp पर कुछ इस तरह की फोटो आईं, जिस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान आकर्षित किया है। इसकी सी.बी.आई. जांच की जाए। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : देखिए, नरेश जी, please allow the Question Hour to proceed.

श्री नरेश अग्रवाल : श्रीमन, क्वेश्चन ऑवर का मतलब यह नहीं है कि एक इम्पोर्टेंट मसले को दबा दिया जाए। इस पर गृह मंत्री जी से हम लोगों को सूचनाएं और सरकार से कुछ जवाब चाहिए। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: The issue has been raised.

श्री नरेश अग्रवाल : सरकार ने जवाब दिया है वह ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Please don't make allegations like that. It is not fair. ...(*Interruptions*)... Please sit down. No, no. ...(*Interruptions*)... One minute, please.

श्री नरेश अग्रवाल : सरकार को स्पष्ट जवाब देना चाहिए सरकार ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : प्लीज सिट डाउन। No, no, one minute please. बैठ जाइए, बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)... नरेश जी, प्लीज। ...(**व्यवधान**)...

श्री नरेश अग्रवाल : अगर यह सरकार इस मसले पर कोई जिम्मेदारी की बात नहीं कर रही है ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: It is not going on record.

श्री नरेश अग्रवाल : हम सदन का बहिष्कार करते हैं।

(*At this stage, the hon. Member left the Chamber.*)

MR. CHAIRMAN: Let us take up Question No. 91. Has the answer been laid on the Table? All right. Now, Shri Tapan Kumar Sen.

SHRIMATI JAYA BACHCHAN: Sir, I would request that the Home Minister should say a few words. Please, Sir.

MR. CHAIRMAN: The Home Minister has already made a statement. ...(*Interruptions*)...

SHRIMATI JAYA BACHCHAN: Sir, I request you to...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: No, the Home Minister has already...

SHRI P. RAJEEVE: Sir, the House is expecting some response. ...(*Interruptions*)... On the basis of the discussion. ...(*Interruptions*)...

श्रीमती जया बच्चन : बात को मत टालिए सर. Sir, this is very important. Let us give ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: I think, the Minister has made a Statement.

SHRI P. RAJEEVE: That is true, Sir. The hon. Home Minister made a Statement but we want his response on the queries raised by the hon. Members. ...(*Interruptions*)... We are grateful to the Home Minister for making the Statement but the Members have raised some issues. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: All right. We shall do it after the Question Hour. ...(*Interruptions*)... We shall do it after the Question Hour.

SHRIMATI JAYA BACHCHAN: Sir, this is not fair... (*Interruptions*).... Sir, I walk out of the House.

श्रीमती कनक लता सिंह (उत्तर प्रदेश): मैं भी सदन से वाकआउट करती हूं।

(*At this stage, some hon. Members left the Chamber.*)

MR. CHAIRMAN: Yes, Mr. Tapan Kumar Sen. ...(*Interruptions*)... Please sit down. ...(*Interruptions*)... Mr. Sen, please go ahead with your question.

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Thank you, Sir. ...(*Interruptions*)...

श्री किरनमय नन्दा (उत्तर प्रदेश) : सर, सभी वाकआउट करके चले गए **...(व्यवधान)...**

SHRI P. RAJEEVE: Sir, it is not an issue of women alone. ...(*Interruptions*)... We have several precedents. ...(*Interruptions*).. Just five minutes' time is needed.

MR. CHAIRMAN: Mr. Rajeeve, why are you doing this? ...(*Interruptions*)... All right. One minute. ...(*Interruptions*)... Let us hear the Leader of the Opposition.

विपक्ष के नेता (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : जया जी, एक मिनट। मैं आप ही की बात कर रहा हूं। Sir, the hon. Home Minister has made a good Statement but the hon. Members want to get his response on some questions. It is a normal practice in this House that whenever there is a Statement by a Minister, hon. Members seek some clarifications.

Since there is constraint of time, I would request that let us go ahead with the

[श्री गुलाम नबी आज़ाद]

Question Hour, but after the Question Hour, the hon. Members should be given the opportunity to ask the questions. ...(*Interruptions*)... But that is the normal practice. ...(*Interruptions*)...

SHRI P. RAJEEVE: Sir, only five minutes are needed ...(*Interruptions*)... The Minister is ready. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN : He has agreed to it. That's it. ...(*Interruptions*)...

SHRI GHULAM NABI AZAD: Then, at the first place, the statement should not have been given in the nick of time. It should have been given at a time when ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: I am sorry ...(*Interruptions*)... It has already been ...(*Interruptions*)...

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार अब्बास नक़वी) : चेयरमैन साहब, आज़ाद साहब, उस समय नहीं थे। लगभग सभी सम्मानित सदस्यों ने सवाल किए और मंत्री जी ने उनका जवाब दिया। उसके बाद 2 बजे से भारी बारिश के कारण देश भर में हुई तबाही से किसानों को हुए नुकसान पर चर्चा फिर शुरू होने वाली है। उसके अलावा अभी माननीय गृह मंत्री जी द्वारा दिया गया जवाब बहुत ही स्पष्ट है।

श्री सभापति : मैंने suggest किया कि क्वेश्चन ऑवर के फौरन बाद अगर कोई क्लैरीफिकेशंस हैं..

श्री शरद यादव (बिहार): सर, यह दो-चार मिनट में हो जाएगा और आपका क्वेश्चन ऑवर भी चल जाएगा और मंत्री जी जवाब भी दे देंगे। उसमें क्या परेशानी है?

गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) : सभापति महोदय, इस घटना के संबंध में मैं सदन को विस्तृत जानकारी दे चुका हूं, लेकिन मैं सदन के सभी सम्मानित सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस घटना की जानकारी प्राप्त होने के बाद मैंने स्वयं ही हर्ट फील किया है। सभापति जी, मुझे स्वयं इस बात पर आश्चर्य हुआ है कि डॉक्युमेंट्री शूट करने के लिए एक ऐसा व्यक्ति जो रेपिस्ट है, उसका इंटरव्यू करने की इज़ाज़त क्यों दी गई? यह ज़ाहिर है कि जब डॉक्युमेंट्री की शूटिंग करने की इज़ाज़त दी जा रही है ...**(व्यवधान)**...

श्रीमती रेणुका चौधरी : आप असल बात पर आइए ...**(व्यवधान)**...

श्री राजीव शुक्ल (महाराष्ट्र): सर, 2013 में ...**(व्यवधान)**... सर, तीन साल हो गए हैं। ...**(व्यवधान)**... फिर अप्रैल, 2014 में रोक लगायी गई। ...**(व्यवधान)**...

श्रीमती रेणुका चौधरी : सर, 7 अप्रैल, 2014 को रोक लगायी गयी थी ...**(व्यवधान)**...

श्री राजनाथ सिंह : सभापति महोदय ..

श्री सभापति : प्लीज, उनकी बात सुन लीजिए। ...**(व्यवधान)**... राजीव जी, प्लीज, वे बोल रहे हैं, उनकी बात सुन लीजिए।

श्रीमती मोहसिना किदवई : सर, यह बड़ा ही गंभीर मामला है। आप इसे दूसरी तरह से लेने की कोशिश मत कीजिए। आप कह रहे हैं कि permission किसने दी ...(**व्यवधान**)...

†**محترمہ محسنہ قدوائی :** سر، یہ بڑا ہی گمبھیر معاملہ ہے۔ آپ اسے دوسری طرح سے لینے کی کوشش مت کیجئے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ پرمیشن کس نے دی ---(مداخلت)۔

श्री सभापति : प्लीज बैठ जाइए, बैठ जाइए।

श्री राजनाथ सिंह : सभापति महोदय, क्या ये सम्मानित सदस्य चाहते हैं कि पूरे मामले की जांच न हो? क्या ये चाहते हैं कि किन परिस्थितियों में यह आदेश दिया गया, इसकी जांच न हो? क्या ये चाहते हैं कि इस में responsibility fix नहीं की जाए? ये क्या चाहते हैं? ...(**व्यवधान**)... सभापति महोदय, मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं इस पूरे मामले की जांच कराऊंगा और जो भी इस के लिए responsible होगा, उसकी responsibility fix करूंगा।

MR. CHAIRMAN: Thank you. ...(*Interruptions*)... We shall now proceed with the Question Hour. Mr. Tapan Kumar Sen. ...(*Interruptions*)... आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए। Please allow the Question Hour to proceed. There shall be no further discussion on this subject. ...(*Interruptions*)... Mr. Tapan Kumar Sen, please continue.

श्रीमती रेणुका चौधरी : हम भी चाहते हैं कि सच सामने आए। आप सच का सामना करिए ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : रेणुका जी, बैठ जाइए।

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Demand for increasing the minimum wages

*91. SHRIMATI GUNDU SUDHARANI: Will the Minister of LABOUR AND EMPLOYMENT be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that major trade unions in the country have put before Government the demand for increasing minimum wages to ₹ 15,000 from the existing ₹ 10,000, if so, the details of the proposal;

(b) what efforts the Ministry is making to amend the Minimum Wages Act, 1948 to implement the above demand;

(c) whether Government is considering universal coverage of the above minimum wages to all employments; and

(d) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

---

†Transliteration in Urdu Script.